3

सरगुजा अंचल के विकास में आएगी तेजी

5

जिद ने बनाया कपिल को सर्वोच्च वकील

6

अवैध शराब के विरुद्ध मालवा में कार्यवाही

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 36 प्रति सोमवार, 13 जनवरी 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में जनता को मिला सुशासन और संबल

अब जनता को मिलेगा पटवारी और तहसीलदार के चक्कर काटने से छुटकारा

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार निरंतर जनता के हित से जुड़े निर्णय कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक संबल देने का कार्य कर रही है। पिछले दिनों आम जनता की सुविधाओं के मद्देनजर विष्णु देव साय सरकार एक अहम फैसला लागू करने की योजना बना रही है। दरअसल सरकार रजिस्ट्री और नामांतरण और बंटवारा सहित जमीन की खरीदी से जुड़े कार्यों में सरलता बरतने के लिये तकनीक का इस्तेमाल करते हुये नया ऐप लांच करने जा रही है। इस ऐप का नाम सुगम दिया गया है। सुगम ऐप के माध्यम से रजिस्ट्री होने के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी आसानी से पूरी हो सकेगी। इस निर्णय के लागू होने के साथ आम जनता को सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। आम जनता को समय की बचत के साथ साथ व्याप्त भ्रष्टाचार व्यवस्था से मुक्ति मिल सकेगी।

भ्रष्ट व्यवस्था से मिलेगी मुक्ति

राज्य के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा सुगम ऐप के माध्यम से रजिस्ट्री का कार्य लागू किया गया था ताकि पूरा कार्य पारदर्शी तरीके से हो सके एवं फर्जी रजिस्ट्री के मामलों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। (शेष पेज 7 पर)

पिता कमलनाथ के सपनों को संरक्षित कर विकास कार्य को गति देने मैदान में उतरे नकुलनाथ

भाजपा नेताओं द्वारा जनता के ऊपर किये जा रहे अत्याचारों को रोकने में महत्वपूर्ण कदम बढ़ायेंगे नकुलनाथ

-विजया पाठक

कहते हैं पिता यदि अपनी आंखों से कोई सपना देखता है तो उसकी चाहत होती है कि उसके उस सपने को उसका बेटा जरूर पूरा करे। यही कारण है कि वह अपने बेटे को शुरू से ही ऐसी शिक्षा देता है कि रास्ते में चाहे जितनी भी कठिनाईयां आयें बेटा उन्हें पाटकर आगे बढ़ने के लिये तैयार रहे। कुछ ऐसे ही सपनों को बुनियादी रूप से आकार देने का काम इन दिनों छिंदवाड़ा के लोकप्रिय नेता और पूर्व सांसद नकुलनाथ कर रहे हैं। दरअसल नकुलनाथ अपने पिता कमलनाथ द्वारा बूंद-बूंद कर सिंचित कर विकसित किये गये छिंदवाड़ा जिले को अब एक नया स्वरूप देने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि कमलनाथ ने जिस छिंदवाड़ा को देश का मॉडल जिला बनाया है भाजपा शासन आते ही उस मॉडल को बर्बाद करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। यही कारण है कि नकुलनाथ अपने पिता से विरासत में मिली इस बुनियाद को भविष्य में संरक्षित रखने के कार्य की योजना बना रहे हैं।

भाजपा नेताओं की लगी नजर

कभी हंसता-खिलखिलाता और चहुं ओर हरियाली से सराबोर छिंदवाड़ा जिले को भाजपा नेताओं की ऐसी नजर लगी कि आज जिले में आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। (शेष पेज 7 पर)

एक बार फिर सुर्खियों में यूनियन कार्बाइड का कचरा

भारी विरोध के बाद बैकफुट पर मध्यप्रदेश सरकार

-विजया पाठक

सेकेंड स्टोरी

पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पीथमपुर में स्थानीय लोगों के भारी विरोध के चलते सरकार बैकफुट पर आ गई है। और सरकार ने फिलहाल कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा पीथमपुर में आया है, तब से इसको लेकर प्रदेश में खूब सियासत हो रही है। पीथमपुर में जलने वाले जहरीले कचरे को लेकर आए दिन कोई न कोई अफवाह फैली। वहीं कांग्रेस भी लोगों के साथ खड़ी नजर आ रही है और पीथमपुर में कचरे को नष्ट करने का विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कचरा निस्तारण के लिए 06 सप्ताह का समय दिया है। 18 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई होनी है। (शेष पेज 2 पर)

एक बार फिर सुर्खियों में यूनियन कार्बाइड का कचरा

(पेज 1 से जारी)

पीथमपुर में विरोध के चलते सरकार ने कचरा निष्पादन के समय मांगा था। सरकार ने अदालत से समय मांगा ताकि "लोगों में विश्वास पैदा किया जा सके और उन्हें तथ्यात्मक जानकारी देकर उनके मिथकों को दूर किया जा सके ताकि वे फर्जी खबरों और बदमाशों और निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई गई गलत सूचनाओं से गुमराह न हों। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कचरे का लोगों और फसल पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी किया गया। वैज्ञानिकों की उपस्थिति में यह कदम उठाया गया। मध्यप्रदेश और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की निगरानी में कचरा पीथमपुर पहुंचा है। किसी को कोई परेशानी न हो यह ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। राजनीतिक चश्मे से देखकर कोई कुछ कहे तो इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। अदालत के निर्णय के बाद यह हो रहा है। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। अदालत के आदेश पर 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्थानीय मिट्टी और 40 प्रतिशत सेवन नेफ्टोल है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जहरीलापन 40 साल में खत्म हो जाता है। इस तरह उन सभी आशंकाओं की समाप्ति हो जाती है। भोपाल के लोग 40 साल से इस कचरे के साथ रहते आ रहे हैं। कचरे के निपटारे के लिए दुनिया में शायद ही किसी ने इतना अध्ययन किया होगा। समय-समय पर किए गए अध्ययन और प्रतिवेदन और 10 टन कचरे को जलाए जाने की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई गई थी। इसके बाद दोबारा 10 टन कचरे को पीथमपुर में जलाया गया था। अगस्त 2015 में यह ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया था। इन सबके बाद पुनः यह उभर कर आया कि कचरे के निपटारे से पर्यावरण को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि 12 कंटेनर और कड़ी सुरक्षा के बीच यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से पीथमपुर पहुंचा दिया गया है। जिसे लेकर पीथमपुर से लेकर इंदौर तक विरोध जताया गया। राजधानी में 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे। वहीं लाखों लोग इससे संक्रमित हुए और आज भी इसका दंश झेल रहे हैं। गैस कांड की वजह से बच्चे कई गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। अब इसके 337 मीट्रिक टन कचरे को जलाने की खबरों से लोग दहशत में हैं। दरअसल, 2015 में सरकार ने इसके 10 टन खतरनाक कचरे को बतौर ट्रायल जलाया था। इससे पैदा हुई 40 टन राख को इंदौर जिले के पीथमपुर में दफनाया गया था लेकिन इससे 08 किमी क्षेत्र का भूजल दूषित हो गया था। वहीं अब सरकार यहां पड़े 337 मीट्रिक टन कचरे को जलाकर डिस्पोज करने जा रही थी। हालांकि, इसका क्या असर होगा, ये कह पाना मुश्किल है। यही वजह है कि जिस जगह पर यह जहरीला कचरा जलाया जाना है, वहां के लोग विरोध पर उतर आए हैं।

साल-दर-साल कचरे का मामला

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पड़े 377 टन जहरीले कूड़े को हटाने के लिए 21 साल की कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। सबसे पहले साल 2004 के अगस्त महीने में भोपाल के रहने वाले आलोक प्रताप सिंह ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की और यूनियन कार्बाइड परिसर में पड़े जहरीले कचरे को हटाने की गुहार लगाई। इसी के साथ पर्यावरण को हुए नुकसान के निवारण की मांग भी की। इसके बाद साल 2005 में हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान के संबंध में एक टास्क फोर्स की समिति का गठन किया। इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि कचरे के सुरक्षित निपटान करने को लेकर अपनी सिफारिशें दें।

अप्रैल 2005 में केंद्रीय रसायन और पेट्रोलिकेमिकल्स मंत्रालय ने एक आवेदन दायर किया और उच्च न्यायालय से कहा कि कचरा हटाने में आने वाला पूरा खर्च उत्तरदायी कंपनी डाउ केमिकल्स, यूसीआईएल से ही वसूला जाए।

जून 2005 में एमपी हाईकोर्ट ने आदेश दिया, इस आदेश के अनुपालन में गैस राहत विभाग ने कचरे को पैक करने और भंडारन करने के लिए रामकी एनवायरो फार्मा लिमिटेड को नियुक्त किया। इसी बीच परिसर में करीब 346 टन जहरीले कचरे की पहचान की गई।

अक्टूबर 2006 में एमपी हाईकोर्ट ने 346 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को अंकलेश्वर (गुजरात) भेजने का आदेश दिया था। वहीं, नवंबर 2006 में हाईकोर्ट ने पीथमपुर में टीएसडीएफ सुविधा के लिए 39 मीट्रिक टन चूना कीचड़ के परिवन का आदेश दिया।

अक्टूबर 2007 में गुजरात सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा अंकलेश्वर स्थित भरूच एनवायर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में जलने में असमर्थता व्यक्त की।

अक्टूबर 2009 में टास्क फोर्स की 18वीं बैठक पीथमपुर में 346 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को भेजने का फैसला किया गया। फैसले के बाद यह काम नवंबर से ही शुरू कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अंकलेश्वर में कचरा भेजना असंभव लग रहा था।

अक्टूबर 2012 में मंत्रियों के समूह ने ट्रायल के तौर पर 10 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर में टीएसडीएफ सुविधा में जलाने का फैसला लिया गया। इसके बाद अप्रैल 2014 में देश के शीर्ष न्यायालय ने पीथमपुर में 10 टन कचरा नष्ट करने की योजना बनाने के लिए आदेश दिया।

दिसंबर 2015 में देश के शीर्ष न्यायालय ने 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर में निपटाने का आदेश दिया। बाद में अप्रैल 2021 में मध्यप्रदेश की सरकार ने इस कचरे के निपटान के लिए टेंडर आमंत्रित किए। नवंबर 2021 में रामकी को टेंडर दे दिया गया।

दिसबंर 2024 में एमपी के हाईकोर्ट ने जहरीले कचरे में निपटान में हो रही देरी पर फटकार लगाई और कहा कि एक महीने के अंदर यहां से कचरा हटाया जाना चाहिए। कोर्ट के फटकार के बाद कवायद तेज की गई।

यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड में गई थीं हजारों जानें

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई त्रासदी को दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। 02 और 03 दिसंबर, 1984 की मध्य रात्रि अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की भोपाल स्थित कीटनाशक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई। भोपाल के लाखों लोग इस जहरीली गैस की चपेट में आ गए। सरकारी आंकड़ों में इस गैस रिसाव से 5479 लोगों की मौत का दावा किया जाता है, लेकिन सामाजिक संगठनों का दावा है कि इस त्रासदी में 10 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी। फैक्ट्री में कचरा 40 साल तक पड़ा रहा और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 03 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों के निर्देशों के बावजूद इसे साफ नहीं करने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की थी। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को इस मामले में निष्क्रिय पड़े रहने के लिए फटकार लगाते हुए, यूनियन कार्बाइड फैक्टी से करीब 337 टन औद्योगिक कचरे को हटाने के लिए 04 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की थी और सरकार से इस संबंध में 06 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट के निर्देश पर मोहन यादव की सरकार ने यूनियन कार्बाइड से 12 ट्रकों में कचरा भरकर पीथमपुर पहुंचाया, जहां जलाकर इसका निपटान होना था। लेकिन स्थानीय लोगों और कुछ सामाजिक संगठनों ने पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी का कचरा जलाए जाने का उग्र विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीथमपुर में कचरा जलाए जाने से आसपास के इलाके में गंभीर प्रदूषण फैल सकता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का खेल तो नहीं यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा?

यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा आख़िर इंदौर के समीप पीथमपुर पहुँचा ही दिया गया। सरकार के सूत्र बताते हैं कि डॉक्टरों, विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों से लेकर स्थानीय नागरिकों और पक्ष-विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद यह कचरा पीथमपुर में ही जलाया जायेगा। ऐसा इसलिये नहीं कि यही सही फ़ैसला है, बल्कि इसलिये कि ये पूरा खेल हज़ारों करोड़ की डीलिंग का भी है। इस पूरे खेल के असली किरदार कौन हैं, यह तो वक्त के साथ पता चलेगा। 02 एवं 03 दिसंबर, 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस लीक हुई थी, जिससे कम से कम 5,479 लोगों की मौत हो गई थी और हज़ारों लोगों को गंभीर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई थीं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फ़ैक्ट्री हमेशा के लिये बंद हो गई और फ़ैक्ट्री को बैंकों से मिला क़र्ज़ NPA होकर डूबने की श्रेणी में आ गया। लोन देते वक्त बैंक ने यूनियन कार्बाइड की जमीन और अन्य संयंत्रों को मॉडगेज कर लिया था, इसलिये बैंकों के पास अपना क़र्ज़ वसूलने का एक मात्र विकल्प था यूनियन कार्बाइड की जमीन की बिकवाली कर कर्ज वसूलना। बैंक यूनियन कार्बाइड की भूमि नीलाम करने की योजना बनाते भी तो कैसे, क्योंकि नीलामी में सबसे बड़ी बाधा इस जमीन पर रखा 347 मैट्रिक टन ज़हरीला कचरा था, जिसके निस्तारण के बिना भूमि को बेच पाना लगभग नामुमकिन था। यहीं से घोटाले का सारा खेल शुरू हुआ और बीजेपी के मध्यप्रदेश से लेकर केन्द्र तक के कुछ नेताओं की नज़र में पूरा मामला आ गया। अब इस जमीन से कचरा हटाना और जमीन हथियाना बीजेपी नेताओं की पहली प्राथमिकता बन गई। बीजेपी के धुरंधर नेताओं ने देश-विदेश एक करते हुए बैंकों से संपर्क किया और जमीन से जहरीला कचरा हटाने के एवज में यह शर्त रखी कि नीलामी में यह जमीन उन्हें/उनके साथियों को ही दी जायेगी। अपना करोड़ों रूपये का कर्ज वसूलने के लिए बैंक ने भी बीजेपी नेताओं को ही जमीन बेचने की शर्त मान ली और पूरा काम बीजेपी नेताओं को ठेके पर दे दिया। बीजेपी नेताओं ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्थानीय लोगों और भूमाफियों से कोर्ट में केस लगवा दिया और फिर अदालत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते रहे। अभी भी जो कचरा भोपाल से पीथमपुर भेजा गया है, उसके पीछे अदालती आदेश का ही हवाला दिया जा रहा है, जबकि अदालती आदेश केवल जनता की आँखों में धूल झोंकने की कोशिश है। मोहन यादव सरकार ने पीथमपुर की कचरा जलाने वाली संस्था मेसर्स पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 29 मई 2024 को ही 20% की राशि 21.37 करोड़ का भुगतान भी कर दिया था। जब पीथमपुर के लोगों ने विरोध शुरू किया तब सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के पीछे अदालत के आदेश का हवाला दिया, जबकि हक़ीक़त में मोहन यादव सरकार ने अदालत के आदेश के पहले ही पूरी प्रक्रिया कर भुगतान तक कर दिया था। मोहन यादव सरकार ने अपना दामन सुरक्षित रखने के लिये अदालत से भी एक आदेश निकलवा दिया ताकि जनता का संदेह बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं पर नहीं जाये।

इन सवालों के जवाब कौन देगा?

- वो कौन लोग थे जो बार-बार अदालत जाकर भोपाल से कचरा कहीं और भेजना चाहते थे?
- अदालत के फ़ैसले के बाद मोहन यादव सरकार ने अप्रील में जाने या अन्य रास्ता खोजने की बजाय रातों रात कचरा पीथमपुर भेजने का विकल्प क्यों चुना?
- इंदौर के प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता के साथ क्यों खड़े नहीं नज़र आये?
- जो कचरा 40 वर्षों से एक जगह पर पड़ा था, ऐसी क्या वजह रही कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के एक वर्ष में ही वो पीथमपुर भेज दिया गया।
- मोहन यादव विशेषज्ञों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? कौनसा प्रेशर है जो पूरे मालवा की जान ख़तरे में डाल दी गई है?
- बीजेपी के वो कौन से नेता है जो इस पूरे मामले के लाभार्थी हैं?
- भोपाल की यूनियन कार्बाइड की जमीन ख़ाली होने के बाद बीजेपी के कौन लोग इस जमीन का इस्तेमाल करने वाले हैं? कुल मिलाकर यह पूरा खेल जमीन माफ़िया, बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों/मंत्रियों की कारगुजारी का है। लाखों लोगों की जान संकट में डालकर ये अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। इन बेईमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मालवा की आने वाली पीढ़ियाँ विकलांग पैदा होंगी या हर घर में कैंसर से मौत होगी। (शेष पेज 7 पर)

रायपुर-अम्बिकापुर-बिलासपुर के लिए नई विमान सेवा से सरगुजा अंचल के विकास में आएगी तेजीः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख शहर हवाई सेवा से जुड़े

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को राज्य के तीन प्रमुख शहरों को एयर कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने केन्द्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत नई विमान सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल के शुभारंभ किया। इस नई विमानसेवा से रायपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर शहर जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विशेष कर सरगुजा संभाग के गौरवपूर्ण क्षण हैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मै धन्यवाद देना चाहता हूं। जिनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में ऐसी विमानन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से उद्योग और व्यापार में तेजी आने के साथ-साथ निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। इस सुविधा से राज्य में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश भी बढ़ेगा। इससे सरगुजा संभाग में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विमान सेवा से सरगुजा संभाग में कनेक्टिविटी रहेगी। उन्होंने सांसद चिंतामणि महाराज को सपत्नीक बोर्डिंग पास देकर स्वागत किया।

सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी विमान सेवा

रीजनल कनक्टिविटी योजना (उड़ान) के तहत यह विमान सेवा सप्ताह में तीन दिन गुरूवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होगी। यह विमान सेवा फ्लाई बिग कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है। इस एयरक्राफ्ट का नाम ट्विन ओट्र है, जिसकी क्षमता 19 सीटर है जिसमें आज 17 यात्रा सवार हुए। यह सेवा भारत सरकार के उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है। श्री चिंतामणि महाराज इस विमान के पहले यात्री बने। शुभारंभ अवसर पर विमान के रनवे पर पहुंचने पर वाटर कैनन से विमान को सैल्यूट दिया गया।

शुरूआती किराया 999 रूपये

नई विमान सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्री कहीं से भी www.flybig.in ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इस सेवा का शुरूआती किराया मात्र 999 रूपये रखा गया है।

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य है अटूट सांस्कृतिक सम्बन्धः मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

-शशि पाण्डे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के चौबे कॉलोनी में आयोजित तीन दिवसीय बृहन्महाराष्ट्र मंडल के 73वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने इस महती अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले मराठी समाज से जुड़े प्रबुद्धजनों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया और समाज के लिए उनके योगदान की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री साय ने मराठी समाज के पुरोधाओं को नमन करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच अटूट रिश्ता है और दोनों के सांस्कृतिक संबंधों में यह बात झलकती है। पड़ोसी राज्य होने के कारण यह जुड़ाव अधिक सहज भी है। साय ने सीपी बरार के दौर का जिक्र करते हुए कहा की उस दौर में दोनों क्षेत्र की राजधानी नागपुर हुआ करती थी और जनप्रतिनिधि मनोनीत होते थे। मेरे दादा स्वर्गीय बुद्धनाथ साय मनोनीत विधायक थे और महाराष्ट्र से सहज जुड़ाव मेरी स्मृतियों में है। साय ने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक बालासाहेब देशपांडे सहित मराठी समाज के मूर्धन्यों का पुण्य स्मरण किया। उन्होंने कहा कि देशपांडे ने जो संकल्प लिया था, आजीवन उसी रास्ते पर चले। आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रयोदशी तिथि के अनुसार आज ही के दिन पिछले साल भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजे थे। उन्होंने सभी को इस पावन दिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस पवित्र दिन आपके अधिवेशन की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से यह अपने उद्देश्यों में सफल होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मराठा मंडल के वार्षिक अधिवेशन की स्मारिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र मंडल के सेवाभावी लोगों का शिक्षा सहित जनसेवा के अन्य क्षेत्रों में विशेष योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य, कला, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण सहित अलग-अलग क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले प्रतिभावान लोगों को इस मंच से सम्मानित कर हम खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का मेल, भाईचारा और एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हमें एकजुट रहकर समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। सनातन धर्म की रक्षा में छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारी सरकार सभी वर्ग के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ नई औद्योगिक नीति से सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास से हम विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ ही पड़ोसी राज्यों की परंपराएं और संस्कृति को जानने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, विधायक सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू, बृहन्महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष मिलिंद महाजन, रायपुर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय काले, डॉ. रामप्रताप सिंह और डॉ. सुनील किरवई सहित समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण

-अमित राय

जगत प्रवाह. बक्सर। जिला पदाधिकारी बक्सर, अंशुल अग्रवाल के द्वारा पूर्वाह्न 10.30 बजे से समाहरणालय बक्सर अन्तर्गत स्थापना शाखा, शस्त्र शाखा, लोक सूचना शाखा, विकास शाखा, जिला भू-अर्जन कार्यालय एवं सामाजिक सुरक्षा कोषांग का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में स्थापना शाखा के कर्मी जगनारायण राय प्रधान लिपिक, हरि नरायण सिंह उ. व. लिपिक, मुकेष कुमार उ. व. लिपिक, गोविन्द कुमार नि.व. लिपिक, सुनील कुमार नि.व. लिपिक, चन्द्र भूषण सिंह नि.व. लिपिक, रीचा कुमारी कार्यपालक सहायक, शैलेश कुमार प्रति.कार्या. परिचारी एवं बबली कुमारी कार्यपालक सहायक व जिला भू-अर्जन कार्यालय के कर्मी कन्हैया लाल सहायक प्रशासी पदाधिकारी, उपेन्द्र कुमार सिंह उ.वि. लिपिक, जगनारायण प्रसाद उ.वि. लिपिक, आदिती प्रिया अमीन एवं मो. महताब अहमद नि.वि. लिपिक व जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कर्मी राजेश कुमार सिंह अनुपस्थित पाए गए। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अनुपस्थित पाए गए सभी कर्मी अपने प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे कि इसके लिए क्यों नहीं उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। स्पष्टीकरण स्वीकृत होने तक अनुपस्थित अवधि का वेतन/मानदेय स्थगित रहेगा।

एम्स भोपाल में संतुलित पोषण पर केंद्रित 'डायटेटिक्स डे 2025' मनाया

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, डायटेटिक्स विभाग ने 10 जनवरी 2025 को 'डायटेटिक्स डे' का आयोजन किया, जो भारतीय डायटेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का विषय 'स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और संतुलित पोषण की ओर मार्गदर्शन करना' था, जिसमें संतुलित आहार, पोषण जागरूकता और जीवनशैली संबंधित बीमारियों की रोकथाम पर जोर दिया गया। डायटेटिक्स डे के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बच्चों के लिए 'नो-फ्लेम कुकिंग प्रतियोगिता' और प्री-टीन के लिए पोषण स्वास्थ्य जांच बूथ शामिल थे। इसके अतिरिक्त, 'स्वस्थ आदतों का पोषणः बच्चे के विकास में सचेत भोजन की महत्ता' पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और विजेता बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने अपने संबोधन में इस आयोजन का महत्व बताते हुए कहा, "डायटेटिक्स डे समाज को संतुलित पोषण और सचेत भोजन के महत्व के बारे में शिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस तरह के प्रयास स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने और पोषण संबंधी विकारों की रोकथाम में सहायक होते हैं।" इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रो. (डॉ.) रजनीश जोशी (डीन-एकेडमिक्स), कर्नल (डॉ.) अजीत कुमार (डिप्टी डायरेक्टर, प्रशासन) और प्रो. (डॉ.) शशांक पुरवार (कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक) उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन डायटेटिक्स विभाग के फैकल्टी इंचार्ज प्रो. (डॉ.) अमित अग्रवाल (आयोजन अध्यक्ष) और एसोसिएट प्रोफेसर, ईएनटी विभाग, डॉ. अंजन साहू (आयोजन सह-अध्यक्ष) के नेतृत्व में किया गया। प्रमुख वक्ताओं में सुश्री अमिता सिंह (कंसल्टेंट, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, नेशनल हॉस्पिटल, भोपाल एवं कार्यकारी समिति सदस्य, आईएपीईएन भोपाल चैप्टर), प्रो. (डॉ.) पंकज गोयल (विभागाध्यक्ष, डेंटिस्ट्री), प्रो. (डॉ.) सीमा पी. महंत (प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन विभाग), डॉ. अनुराधा कुशवाह (बाल मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सा विभाग) और प्रो. (डॉ.) शिखा मलिक (विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग) शामिल रहे। इस आयोजन को आयोजन सचिव सुश्री भावना अहरवार (सीनियर डाइटिशियन) ने सह-संगठन सचिव सुश्री संयुक्ता गौर और सुश्री साची सोनकर (डाइटिशियन) के साथ सफलतापूर्वक आयोजित किया।

सम्पादकीय

बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लगभग एक महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है जोर शोर से घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर सहित देश के प्रमुख महानगरों तथा देश के विशेष समुदाय की सैकड़ों बस्तियों में घुसपैठिये अवैध रूप से बस गए हैं। लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिये और रोहिंग्या देश के लिये गंभीर सुरक्षा के लिये खतरा बन चुके हैं। राजनैतिक कारण और कमजोर इच्छाशक्ति के चलते इस गंभीर विषय की अनदेखी की की गई। शायद ही भारत का कोई भी बड़ा शहर, कस्बा हो जहां संदिग्ध रूप से कुछ बाहरी लोग हाल ही में न बसे हो। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1914 में भारत में अनुमानित बांग्लादेशियों की संख्या लगभग दो करोड़ बताई थी।

इस प्रकरण का दुखद पहलू यह है कि घुसपैठ का मुद्दा केवल चुनाव के दौरान जोरशोर से उठता है परंतु चुनाव के बाद इसकी तीव्रता धूमिल हो जाती है। यदि हम देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो सबसे प्रमुख बात तो यह है कि दिल्ली सरकार और पुलिस से यदि पूछा जाए कि दिल्ली में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो इसका उत्तर गोलमोल ही मिलता है। शायद राज्यों की पुलिस को भी नहीं पता कि कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? हालांकि हाल ही में एलजी के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा घुसपैठियों, रोहिंग्याओं के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अच्छी बात है अब आप शासित दिल्ली नगर निगम ने भी अपनी तरफ से अभियान शुरू करने का फैसला लिया है।

एलजी ने दिल्ली पुलिस को अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके आगे की कार्रवाई करने के लिये कहा है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शहर में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई अनधिकृत कब्जा न हो जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। इस दौरान बीते 22 दिसंबर तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जांच के दौरान मात्र 175 घुसपैठिये ही चिन्हित किये जा सके हैं। चूंकि घुसपैठियों के खिलाफ अभियान सीमित अवधि के लिए है ऐसे में घुसपैठिये दिल्ली छोड़कर आसपास के जिलों गाजियाबाद आदि में भाग सकते हैं। ऐसे में फिर इस अभियान पर पलीता लगा सकता है। इसलिए जरूरत है एक समेकित, कारगर और दीर्घकालीन अभियान शुरू करने की।

इस प्रकरण का दूसरा नाकारात्मक पहलू यह है कि इस मुद्दे पर आप और भाजपा के बीच राजनैतिक बयानबाजी शुरू हो गई है जिससे इस अभियान की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है आप का यह बयान कि घुसपैठियों के बहाने भाजपा पूर्वांचल निवासियों पर निशाना साध रही है जो कि बिल्कुल तथ्य से परे है। ऐसे बयानों से अभियान की तीव्रता बाधित हो सकती है। जब एलजी और एमसीडी दोनों अपनी अपनी ओर से घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रहे है तो ऐसे में विरोधाभासी बयान की क्या आवश्यकता है।

सियासी गहमागहमी

शिवराज के फैसलों पर चाकू चलाते मोहन

मध्यप्रदेश में 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी के सरताज बने शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिये गये निर्णयों पर एक के बाद एक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चाकू चलाते जा रहे हैं। पहले रातापानी अभ्यारण्य को नेशनल सेंचुरी बनाने का फैसला लेकर मोहन यादव ने भरे मंच से यह बात कह भी दी कि कुछ लोगों ने 17 वर्ष लगा दिये रातापानी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में। इतना ही नहीं अब डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना से डेढ़ लाख से अधिक महिलाओं को बाहर का रास्ता दिखाने का निर्णय लिया है। शिवराज सिंह चौहान के फैसलों पर जिस ढंग से मोहन यादव चाकू चला रहे हैं यह देख हर कोई हैरत में है। क्योंकि एक ही पार्टी के नेता आपस में मिलकर एक दूसरे के फैसलों को इस तरह से काट रह हैं यह बात किसी को समझ नहीं आ रही है।

बड़े नेताओं का दखल किया खत्म

मध्यप्रदेश में संगठन चुनावों में बीजेपी में खूब उथल-पुथल हुई। पार्टी संगठन में वर्चस्व स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के मंत्री और सांसद, विधायकों में खासी खींचातानी मची। बीजेपी संगठन ने चुनाव के पूर्व साफ कहा था कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी, मंत्री, विधायक, सांसद या जिलाध्यक्ष की पसंदगी के आधार पर पद नहीं दिया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी की नीति के उलट ज्यादातर मंडल अध्यक्ष विधायकों, सांसदों के चहेते ही हैं। ऐसे में हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी में अब जिलाध्यक्षों के चयन में प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर केंद्रीय मंत्रियों शिवराजसिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि का सीधा दखल समाप्त कर दिया गया है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में हमारे कई जवानों और वाहन चालक के शहादत की ख़बर सुनकर बेहद दुख हुआ।

शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी @priyankagandhi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएँ।

आपके उत्तम स्वास्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

आईएएस की नौकरी छोड़ खुद की लॉ फर्म शुरू करने की जिद ने बनाया कपिल को सर्वोच्च वकील

समता पाठक/जगत प्रवाह

कपिल सिब्बल एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ हैं। सिब्बल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कई बार हाई-प्रोफाइल मामलों का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें भारत के सबसे शीर्ष वकीलों में से एक माना जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। कपिल सिब्बल ने मई 2022 को कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। सिब्बल ने दिल्ली सेंट जॉन्स हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा हासिल की। इसके बाद 1964 में सेंट स्टीफंस कॉलेज से एलएलबी की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1969 में इसी कॉलेज से इतिहास विषय में एमए की डिग्री हासिल की। 1973 में उनका चयन आईएएस के लिए हुआ था। लेकिन उन्होंने इस प्रतिष्ठित सेवा में जाने से इनकार कर दिया और खुद का लॉ फर्म स्थापित करने का फैसला किया। 1977 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से उन्होंने कानून में एलएलएम की डिग्री हासिल की थी। बतौर राजनेता कपिल सिब्बल ने यूपीए शासनकाल के दौरान कई अहम मंत्रालयों का कामकाज संभाला था। वो करीब तीन दशक तक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे थे। 16 मई 2022 को उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। सिब्बल ने आईएएस की परीक्षा क्लियर करने के बाद भी उसे ज्वाइन नहीं किया था। बाद में उन्होंने अपनी लॉ फर्म खोल ली थी। सिब्बल 1989-1990 तक देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे थे। वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तीन पर अध्यक्ष रहे हैं।

सिब्बल सबसे पहले 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वह 2000-2002 तक कांग्रेस संसदीय दल के सचिव रहे। 2004 वह पहली बार दिल्ली से लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद उन्हें यूपीए-1 के दौरान उन्हें केंद्रीय विज्ञान और तकनीक मंत्री बनाया गया था। 2009 में वह दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री बनाया गया। 2011 में उन्हें केंद्रीय संचाल मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। 5 मई 2016 को वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 25 मई 2022 को वह समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे।

कपिल सिब्बल कई अहम मामलों में विपक्षी दलों या केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे की पैरवी करते रहे हैं। राम मंदिर मामले में सिब्बल ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सरकार के खिलाफ पैरवी की थी। सिब्बल ने तीन तलाक पर सरकार के खिलाफ पैरवी की थी। सिब्बल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उतरे थे। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि तीन तलाक पर बैन लगाना ठीक नहीं है क्योंकि यह आस्था से जुड़ा मामला है। पर सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की दलील को खारिज करते हुए तीन तलाक पर रोक लगा दी थी। सिब्बल ने CAA-NRC मामले में भी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उतरे थे। सीएए के खिलाफ 2019 में सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इंदिरा जयसिंह, सलमान खुर्शीद समेत कई नामी वकीलों ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखी थीं।

स्वामी विवेकानंदः युवा भारत के प्रेरणास्रोत

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

स्वामी विवेकानंद की जयंती यानी 12 जनवरी, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक ऐसा दिन जब हम भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को याद करते हैं। उनके विचारों ने भारत को एक नई दिशा दी और युवाओं के मन में देशभक्ति और आत्मविश्वास का बीज बोया। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार थे, एक आंदोलन थे। उनके आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने पहले थे। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को सिखाया कि वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। उन्होंने कहा था, "उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।" उनकी इसी प्रेरणा ने लाखों युवाओं को सफलता के शिखर पर पहुंचाया। युवा दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि युवाओं के हाथों में ही देश का भविष्य है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का भाषण एक ऐतिहासिक क्षण था। उनके इस भाषण ने भारत को विश्व पटल पर एक नए सिरे से स्थापित किया। इस भाषण ने दुनिया को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद ने देश के आध्यात्म, शिक्षा और स्वाभिमान को विश्व पटल पर अंकित किया। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के वे आदर्श प्रतिनिधि हैं। जिनकी प्रेरणाएं हमें आज भी मार्ग दिखाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी में अपार शक्ति है। हमें बस उस शक्ति को पहचानना है और उसका उपयोग करना है। शिकागो में जब विवेकानंद को दुनिया ने सुना तो जाना कि भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ है जो दिशाहारा मानवता को सही दिशा देने में समर्थ है। शिकागो में विवेकानंद ने कहा था "मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते बल्कि, हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी"। इसका अर्थ यह है कि विवेकानंद भी भारत की सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को दुनिया से परिचित कराने में विवेकानंद का अभूतपूर्व योगदान था।

''भाईयों एवं बहनों'' कहकर किया संबोधित।

वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरू के रूप में स्वामी विवेकानंद का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के उद्बोधन के कारण हुआ। इस उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद द्वारा सभी को ''भाईयों एवं बहनों'' कहकर संबोधित किए जाने ने सभी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे संत रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की, जो आज भी अपना काम कर रहा है।

युवा दिवस : 12 जनवरी

स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी 1984 को युवा दिवस की घोषणा की गई थी। इसके बाद से हर साल इस दिन युवा दिवस मनाया जाता है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। विशेषकर भारतीय युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद से बढ़कर दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता जिसने विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी हो। उन्होंने हमें जो स्वाभिमान दिया है वह उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त कर हमारे अंदर आत्मसम्मान और अभिमान जगा देता है। स्वामीजी ने जो लिखा वह हमारे लिए प्रेरणा है। यह आने वाले लंबे समय तक युवाओं को प्रेरित व प्रभावित करता रहेगा।

विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है लेकिन विवेकानंद के सिद्धांत पूरी दुनिया में 12 महीनों के 365 दिन प्रासंगिक हैं। जिस वेदांत को उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में रचा उसे उन्होंने जीवन पर्यंत अपनाया भी। वेदांत एक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवहारिकता के रूप में विवेकानंद के जीवन में था। इसीलिए अपने जीवन काल में विवेकानंद इतना प्रभाव उत्पन्न कर पाए। उन्होंने भारतीय वांग्मय और भारतीय धर्म-संस्कृति का ही विश्व को परिचय नहीं कराया बल्कि सार्वभौमिक सहिष्णुता के उस सिद्धांत को संसार के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश भी की। विवेकानंद की जयंती पर जरूरत है प्रज्ञावान बनने की, स्वयं को पहचानने की, अपनी आयु से ऊपर उठकर विचार करने की। आप सभी को स्वामी विवेकानंद की जयंती की अनेकानेक शुभकामनाएं।

पर्यावरणीय खतरों से बचने के लिए उठाने होंगे ठोस कदम

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

आज दुनिया तेजी से बदल रही है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, और बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई, और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं मानव जीवन के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा कर रही हैं। इन खतरों से बचने और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाना समय की मांग है। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती के रूप में हमारे सामने है। जलवायु परिवर्तन का असर आज हर कोने में देखा जा सकता है। वैश्विक तापमान में वृद्धि, बर्फ की परतों का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना और अत्यधिक मौसमी घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़ और सूखा इसका उदाहरण हैं। यदि इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भयावह होगा। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलविद्युत ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग सीमित करके इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देनी होगी। वायु प्रदूषण से लड़ाई युद्ध स्तर पर करना होगा। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण हर साल लाखों लोग असमय मृत्यु का शिकार होते हैं। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, और कचरा जलाने जैसी गतिविधियां इस समस्या को बढ़ा रही हैं। इसके समाधान के लिए उद्योगों में कड़े मानक लागू करने होंगे। वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों का पालन करना और ईंधन के स्वच्छ विकल्प अपनाना आवश्यक है। साथ ही, हरित क्षेत्र बढ़ाने और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जल संकट और जल प्रदूषण एक और बड़ी चुनौती है। जल संकट आज एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन और उनका प्रदूषण जल संकट को और गंभीर बना रहे हैं। गंदा जल नदियों और झीलों में छोड़ा जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, बल्कि पीने के पानी की कमी भी बढ़ रही है। पानी बचाने के लिए जल प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करना और जल स्रोतों को साफ रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही, औद्योगिक कचरे को जल स्रोतों में फेंकने पर सख्त प्रतिबंध लगाना होगा। इनके अलावा वनों की कटाई और जैव विविधता का संरक्षण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन हमारी धरती के फेफड़े हैं। लेकिन शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण वनों की कटाई तेजी से हो रही है। इससे न केवल वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि वन्यजीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। वनों की कटाई को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने होंगे। वृक्षारोपण अभियानों को बड़े पैमाने पर चलाना और वनों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना आवश्यक है। इसके अलावा, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़ानी होगी।

प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण भारत सहित विश्व स्तर पर तुरंत करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। यह न केवल जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, बल्कि जलीय जीवों के जीवन को भी संकट में डालता है। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सिंगल-यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना होगा। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण बढ़ाने और इसके वैकल्पिक विकल्पों जैसे कपड़े और कागज के बैग को बढ़ावा देना चाहिए। हरित जीवनशैली अपनाने की आवश्यकता है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। पर्यावरणीय खतरों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जीवनशैली में बदलाव करना होगा। ऊर्जा की बचत, पानी का मितव्ययता से उपयोग और कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी छोटी-छोटी आदतें, जैसे बिजली बंद रखना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना, बड़े बदलाव ला सकती हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देकर बच्चों में जागरूकता पैदा करना भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण में सरकार और समाज दोनों की भूमिका अहम है। सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस नीतियां बनानी चाहिए। वहीं, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सक्रिय रूप से इन नीतियों का पालन करना होगा।

तिब्बत में आए भूकंप के मायने

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

हिमालय के उत्तरी तलहटी में स्थित चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पवित्र नगरों में से एक शिगात्से के निकट 6.8 तीव्रता के भूकंप ने 126 लोगों के प्राण लील लिए और 188 घायल हुए हैं। पड़ोसी देश नेपाल और भारत में भी इसके झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तिंगरी काउंटी में था, जो हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट क्षेत्र का उत्तरी द्वार माना जाता है। हालांकि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने भूकंप की तीव्रता 7.1 आंकी है। इसमें 1000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वास्तविक नुकसान कितना हुआ है, इसका अधिकारी आंकलन कर रहे हैं। भूकंप से तिब्बत में किसी बांध या जलाशय को हानि नहीं पहुंची हैं, लेकिन गौरतलब है कि भूकंप ने भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना ने भारत और बांग्लादेश को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों में टकराव के कारण चीन के दक्षिण-पश्चिम हिस्से नेपाल और उत्तर-भारत में अकसर भूकंप आते रहते हैं।

तिंगरी में आया यह भूकंप ल्हासा भूखंड के रूप में जाने जाने वाले हिस्से में दरार के कारण आया है। 1950 के बाद ल्हासा भूखंड में छह या उससे अधिक तीव्रता के 21 भूकंप आए हैं। इनमें सबसे बड़ा 2017 में मैनलिंग में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। मैनलिंग तिब्बत की यारलुंग जंगबो नदी के निचले हिस्से में स्थित है। इसी नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। चीन यहीं दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की घोषणा कर चुका है। 2015 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। जिसमें लगभग 9000 लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। मृतकों में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में हिमस्खलन की चपेट में आकर 18 लोग मारे गए थे। माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में इस समय ठंड अधिक होने के कारण पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित है। शिगास्ते भारत की सीमा के निकट है, इस पवित्र शहर को शिगाजे नाम से भी जाना जाता है।

हालांकि भूकंप की चेतावनी संबंधी प्रणालियां अनेक देशों में संचालित हैं लेकिन वह भू-गर्भ में हो रही दानवी हलचलों की सटीक जानकारी समय पूर्व देने में लगभग असमर्थ हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देने वाले देशों अमेरिका, जापान, भारत, नेपाल, चीन और अन्य देशों में भूकंप आते ही रहते हैं। इसलिए यहां लाख टके का सवाल उठता है कि चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने का सपना और पाताल की गहराइयों को नाप लेने का दावा करने वाले वैज्ञानिक आखिर पृथ्वी के नीचे उत्पात मचा रही हलचलों की जानकारी प्राप्त करने में क्यों नाकाम हैं? जबकि वैज्ञानिक इस दिषा में लंबे समय से कार्यरत हैं। अमेरिका ने तो अंतरिक्ष में ऐसा उपग्रह भी तैनात कर दिया है, जो संभावित भूकंप आने की चेतावनी देने के लिए ही क्रियाशील है।

दरअसल दुनिया के नामचीन विषेशज्ञों व पर्यावरणविदों की मानें तो सभी भूकंप प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि उन्हें विकराल बनाने में मानवीय हस्तक्षेप षामिल है। प्राकृतिक संसाधनों के अकूत दोहन से छोटे स्तर के भूकंपों की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भविष्य में इन्हीं भूकंपों की व्यापकता और विकरालता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। पहले 13 सालों में एक बार भूकंप आने की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब यह घटकर 4 साल हो गई है। अमेरिका में 1973 से 2008 के बीच प्रति वर्ष औसतन 21 भूकंप आए, वहीं 2009 से 2013 के बीच यह संख्या बढ़कर 99 प्रति वर्ष हो गई। यही नहीं आए भूकंपों का वैज्ञानिक आंकलन करने से यह भी पता चला है कि भूकंपीय विस्फोट में जो ऊर्जा निकलती है, उसकी मात्रा भी पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हुई है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में जो भूकंप आया था, उनसे 20 थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बमों के बराबर ऊर्जा निकली थी। यहां हुआ प्रत्येक विस्फोट हिरोशिमा-नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। जापान और फिर क्वोटो में आए सिलसिलेवार भूकंपों से पता चला है कि धरती के गर्भ में अंगड़ाई ले रही भूकंपीय हलचलें महानगरीय आधुनिक विकास और आबादी के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रही हैं। ये हलचलें भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की धरती के नीचे भी अंगड़ाई ले रही हैं। इसलिए इन देशों के महानगर भी भूकंप के मुहाने पर खड़े हैं।

भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया इस अभिशाप को झेलने के लिए जब-तब विवश होती रही है। बावजूद हैरानी इस बात पर है कि विज्ञान की आश्चर्यजनक तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक ईजाद करने में असफल रहे हैं, जिससे भूकंप की जानकारी आने से पहले मिल जाए। भूकंप के लिए जरूरी ऊर्जा के एकत्रित होने की प्रक्रिया को धरती की विभिन्न परतों के आपस में टकराने के सिद्धांत से आसानी से समझा जा सकता है। ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि करीब साढ़े पांच करोड़ साल पहले भारत और आस्ट्रेलिया को जोड़े रखने वाली भूगर्भीय परतें एक-दूसरे से अलग हो गईं और वे यूरेशिया परत से जा टकराईं। इस टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आई और धरती की विभिन्न परतों के बीच वर्तमान में मौजूद दरारें बनीं। हिमालय पर्वत उस स्थल पर अब तक अटल खड़ा है, जहां पृथ्वी की दो अलग-अलग परतें परस्पर टकराकर एक-दूसरे के भीतर घुस गई थीं। परतों के टकराव की इस प्रक्रिया की वजह से हिमालय और उसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। इसी प्रायद्वीप में ज्यादातर एशियाई देश बसे हुए हैं।

वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक क्रियाओं के कारण भी भूकंप आते हैं। भूकंपों की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किमी भीतर होती है। इससे यह वैज्ञानिक धारणा भी बदल रही है कि भूकंप की विनाशकारी तरंगें जमीन से कम से कम 30 किमी नीचे से चलती हैं। ये तरंगे जितनी कम गहराई से उठेगी, उतनी तबाही भी ज्यादा होगी और भूकंप का प्रभाव भी कहीं अधिक बड़े क्षेत्र में दिखाई देगा। लगता है अब कम गहराई के भूकंपों का दौर चल पड़ा है। मैक्सिको में सितंबर 2017 में आया भूकंप धरती की सतह से महज 40 किमी नीचे से उठा था। इसलिए इसने भयंकर तबाही का तांडव रचा था। तिब्बत में आए इस भूकंप की गहराई तो मात्र 10 किमी आंकी गई है।

दरअसल सतह के नीचे धरती की परत ठंडी होने व कम दबाव के कारण कमजोर पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब चट्टानें दरकती हैं तो भूकंप आता है। कुछ भूकंप धरती की सतह से 100 से 650 किमी के नीचे से भी आते हैं, लेकिन तीव्रता धरती की सतह पर आते-आते कम हो जाती है, इसलिए बड़े रूप में त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती। दरअसल इतनी गहराई में धरती इतनी गर्म होती है कि एक तरह से वह द्रव रूप में बदल जाती है। इसलिए इसके झटकों का असर धरती पर कम ही दिखाई देता है। बावजूद इन भूकंपों से ऊर्जा बड़ी मात्रा में निकलती है। धरती की इतनी गहराई से प्रगट हुआ सबसे बड़ा भूकंप 1994 में बोलिविया में रिकॉर्ड किया गया है। पृथ्वी की सतह से 600 किमी भीतर दर्ज इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई थी। इसीलिए यह मान्यता बनी है कि इतनी गहराई से चले भूकंप धरती पर तबाही मचाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चट्टानें तरल द्रव्य के रूप में बदल जाती हैं।

प्राकृतिक आपदाएं अब व्यापक व विनाशकारी साबित हो रही हैं, क्योंकि धरती के बढ़ते तापमान के कारण वायुमंडल भी परिवर्तित हो रहा है। अमेरिका व ब्रिटेन समेत यूरोपीय देषों में दो षताब्दियों के भीतर बेतहासा अमीरी बढ़ी है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण इसी अमीरी की उपज है। यह कथित विकासवादी अवधारणा कुछ और नहीं, प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन कर, पृथ्वी को खोखला करने के ऐसे उपाय हैं, जो ब्रह्माण्ड में फैले अवयवों में असंतुलन बढ़ा रहे हैं। इस विकास के लिए पानी, गैस, खनिज, इस्पात, ईंधन और लकड़ी जरूरी हैं। नतीजतन जो कॉर्बन गैसें बेहद न्यूनतम मात्रा में बनती थीं, वे अब अधिकतम मात्रा में बनने लगी हैं। न्यूनतम मात्रा में बनी गैसों का षोशण और समायोजन भी प्राकृतिक रूप से हो जाता था, किंतु अब वनों का विनाश कर दिए जाने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल में इकतरफा दबाव बढ़ रहा है। इस कारण धरती पर पड़ने वाली सूरज की गर्मी प्रत्यावर्तित होने की बजाय, धरती में ही समाने लगी है। गोया, धरती का तापमान बढ़ने लगा, जो जलवायु परिवर्तन का कारण तो बना ही, प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन रहा है। ऐसे में सीमेंट, लोहा और कंक्रीट के भवन जब गिरते हैं, तो मानव त्रासदी ज्यादा होती है। जैसे की हमें अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में लगी आग में देखने में आ रहा है।

अवैध शराब के विरुद्ध इटारसी एवं सिवनी मालवा में कार्यवाही, 35 लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब एवं 1850 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त

-नरेन्द्र दीक्षित
जगत प्रवाह.

नर्मदापुरम। कलेक्टर जिला नर्मदापुरम सोनिया मीना के अवैध शराब विक्रय, निर्माण, के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन पर जिला नर्मदापुरम में अवैध मदिरा परिवहन, संग्रहण, विक्रय एवं निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत इटारसी में आबकारी टीम द्वारा को ग्राम भूमकापुरा, रैसल पाठा एवं केसला में कार्यवाही की गई। कार्यवाही की गई। जप्त सामग्री 35 लीटर हाथ भट्टी मदिरा महुआ लहान 1050 किलोग्राम जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत 112000/ है। आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 3 प्रकरण कायम किया है। सिवनी मालवा आबकारी टीम द्वारा कोयलाझीर दुर्गम जंगल एवं फैल मोहल्ला सिवनी मालवा क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही में 800 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रकरण कायम किया है। जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत 80000/- है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक राजेश साहू, आबकारी उपनिरीक्षक हेमन्त चौकसे, आरक्षक गोपाल रघुवंशी, राजेश गौर एवं दुर्गेश पठारिया आदि आबकारी स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जय अंबे इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस को मध्य प्रदेश में ठेका है पर ठेकेदार के पायलेटों द्वारा की जा रही संचालित फर्जी आईडी लेकर एम्बुलेंस

-अमित राजपूत,

जगत प्रवाह. सागर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 108 निशुल्क सेवा एम्बुलेंस का टेंडर मध्यप्रदेश में जय अंबे इमरजेंसी एंबुलेंस सर्विसिंग कंपनी को दिया गया है और निशुल्क एंबुलेंस सुविधा संचालित की जा रही है लेकिन सागर जिले में 2 जनवरी को मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर से आई 108 एम्बुलेंस जो कि फर्जी तरीके से पायलट द्वारा फर्जी आईडी लेकर मुनाफा के लिए जान का सौदा रीडिंग बढ़ाने के लिए ड्राइवर बिना मरीज के दौड़ा रहे 108 एम्बुलेंस। भोपाल से लेकर सागर नरसिंहपुर के 108 के अधिकारियों की मिलीभगत से मरीजों के नाम पर फर्जी आईडी लेकर एंबुलेंस कंपनी और कंपनी में बैठे अधिकारियों और ड्राइवरों द्वारा मुनाफा के लिए मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ड्राइवर का कहना है कि यदि एंबुलेंस रोज 400 किलोमीटर से कम दौड़ाओ तो नौकरी और वेतन पर संकट हो जाएगा इसके लिए 108 एंबुलेंस पायलटों को अधिकारियों द्वारा धमकाया भी जाता है।

फर्जी कॉल पर घूम रही है एंबुलेंस

सागर के देवरी विधानसभा क्षेत्र के सिंगपुर गांव में रहने वाले हरिओम पिता लखन लाल पटैल नामक मरीज के नाम से नरसिंहपुर जिले के बड़े गुड्डू केवनी गांव जो कि नरसिंहपुर जिले में आता है उनके मोबाइल नंबर से संपर्क तवर 6266224620 से 108 एंबुलेंस को डायल कर के उल्टी की पीड़ा होने पर परिजनों द्वारा 108 एंबुलेंस को 2 जनवरी को करीब 10:02 बजे कॉल किया। इस गांव से अस्पताल तक महज आधा घंटे में पहुंचा जा सकता है पर एंबुलेंस नरसिंहपुर जिले से चलकर सागर की देवरी के सिंगपुर गांव में पहुंची। जिसकी रीडिंग 419763 चुकी फर्जी कॉल पर यह 108 एम्बुलेंस मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सुआतला से पायलट द्वारा 108 एंबुलेंस सीजीएनएस 2476 केस आईडी नंबर 8724 समय 10 बजकर 2 मिनिट पर केस आईडी लेकर पायलट द्वारा नरसिंहपुर जिले सागर जिले की सीमा में 108 एम्बुलेंस निकली। क्योंकि फर्जी कॉल पर घूम रही थी एम्बुलेंस 10:02 बजे निकली और 11.33 पर देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। अब आप सोच रहे होंगे कि यह माजरा क्या है तो हम आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले में संचालित हो रही 108 एंबुलेंस सुविधा का लाभ लेने के लिए बड़े गुड्डू नामक व्यक्ति द्वारा अपने परिजन कोमल सिंह जोकि नरसिंहपुर जिले के कैवनी गांव के रहने वाले व्यक्ति को उल्टी दस्त होने पर 108 एंबुलेंस सुविधा को कॉल किया गया था मगर समय पर 108 एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर वह अपने निजी वाहन से नरसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे तो वही जब हमारे संवाददाता द्वारा बड़े गुड्डू से फोन पर संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं आने के कारण हम अपने निजी वाहन से इलाज कराने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे।

इनका कहना है

मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कार्रवाई करेंगे, यह तो गंभीर मामला है मुनाफा के लिए मरीजों की जान संकट में नहीं डाली जा सकती। इस मामले में आपके द्वारा जो भी प्रमाण हो मुझे भिजवा दीजिये। मैं जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा।

राजेंद्र शुक्ला, उपमुख्यमंत्री एवं सागर जिला प्रभारी मंत्री

आपके द्वारा 108 एम्बुलेंस पायलेटों के द्वारा फर्जी केस आईडी का मामला संज्ञान में आया है। जांच करवा कर कार्रवाई करवाती हूं।

डॉ. ममता तिमोरी, सीएमएचओ, सागर

आपके द्वारा 108 एम्बुलेंस पायलेटों एवं अन्य जिलों से आ रही 108 एम्बुलेंस में फर्जी केस आईडी का मामला संज्ञान में आया है। मैं तत्काल ही जिला अधिकारियों से बात करता हूं और कार्रवाई करवाता हूं।

हर्ष यादव, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार

एक बार फिर सुर्खियों में यूनियन कार्बाइड का कचरा

(पेज 2 से जारी)

इनका कहना है-

इस तरह का कचरा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। 25 साल के बाद उसमें कुछ भी खतरनाक नहीं बचता है। यह तथ्यों पर आधारित बात है। इस मामले में प्रशासन की भी कहीं न कहीं चूक हुई है। सही तरीके से बातों को जनता के बीच में नहीं रखा जा सका। जिसके चलते जनता इस पर रोष प्रकट कर रही है और हम कोर्ट के सामने जनता का पक्ष रखेंगे। अभी कचरे को सिर्फ पहुंचाया गया है, उसे जलाया नहीं जाएगा।

वीडी शर्मा, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश बीजेपी

मुख्यमंत्री से लेकर अब अधिकारी तक दावा कर रहे हैं कि कचरे की विषाक्तता खत्म हो गई लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री ने कभी इसका अध्ययन किया है। इस तरह के बयान बताते है कि सरकार की इसको लेकर गंभीरता कम है। आखिर यूनियन कार्बाइड की जमीन को कौन खरीदना चाहता है। स्थानीय स्तर पर विरोध के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 25 साल में कचरे का जहर अपने आप खत्म हो जाता है। यदि इसका जहर खत्म हो गया तो फिर सरकार उसे पीथमपुर में ही क्यों जला रही है। इस कचरे को भोपाल में ही जलाया जा सकता है। आखिर इसको जलाने पर सरकार 121 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। आखिर गैस त्रासदी के नाम पर सरकार 05 हजार करोड़ का बजट क्यों रखती आ रही है।

जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मप्र

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में जनता को मिला सुशासन और संबल

(पेज 1 से जारी)

सुगम ऐप के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनाई गई है। आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही बहुत से बदलाव किए गए है। जल्द ही रजिस्ट्री के साथ नामांतरण को लेकर सकारात्मक बदलाव लागू होंगे। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण होने से बेवजह चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी एवं दशकों से व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था से भी मुक्ति मिलेगी।

90 दिन का इंतजार होगा खत्म

विष्णु देव साय सरकार का सुशासन की दिशा में यह बड़ा कदम साबित होगा। जनता के लिए विष्णु देव साय सरकार द्वारा दी जाने वाली बड़ी राहत होगी। प्रदेश भर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण का प्रोसेस भी ऑनलाइन हो जायेगा। लोगों की परेशानी कम होने के साथ समय का अपव्यय रुकेगा। काम में पारदर्शिता आएगी। आम जनता को नामांतरण के लिए भटकने से मुक्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग में अब तक यह बड़ा बदलाव साबित होगा। सुगम एप में रजिस्ट्री की गई भूमि का विस्तार से रिकॉर्ड,दर्ज होते ही नामांतरण हेतु पटवारी एवं तहसीलदार का प्रोसेस शुरू हो जायेगा। रजिस्ट्री के बाद त्वरित नामांतरण की प्रक्रिया हेतु सुगम एप में ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रदेश भर में रोजना 08 हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री हेतु खरीदार को अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए 30 दिनों से 90 दिन तक इंतजार करना पड़ता है।

तहसील और पटवारी के कार्यालय के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

तहसील और पटवारी कार्यालय में चक्कर भी लगाने पड़ते है। इन सभी परेशानियों के मद्देनजर राजस्व विभाग तत्काल नामांतरण की सुविधा हेतु बड़ा बदलाव करेगा। सुगम ऐप में रजिस्ट्री होने के बाद पूरी पादर्शिता के साथ नामांतरण का प्रोसेस शुरू होगा। भुइंया रिकॉर्ड को सुगम ऐप से जोड़ा जा चुका है। जो रिकॉर्ड इसमें दर्ज होगा, उसके आधार पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी। रजिस्ट्री के दौरान ही गड़बड़ी की सभी आशंकाओं को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में जब राजस्व रिकॉर्ड सही होने पर ही रजिस्ट्री होगी और 24 घंटे में नामांतरण भी हो जाएगा। अभी रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण कराने के लिए तहसील कार्यालय जाना पड़ता है और वहां आवेदन देना होता है।

कांग्रेस के नेता जेब भरते थे, हम जनहित का काम करते हैं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ कुतर्क करना जानते हैं काम करना नहीं जानते। महापौर चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि क्या महापौर ओर अध्यक्ष के चुनाव पहले प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होते थे, क्या कांग्रेस की सरकारों के समय ऐसा नहीं हुआ। अब कांग्रेस के नेता दो तरह की बातें क्यों करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जीत चुराने के लिए जनता के अधिकारों को छीना। हमने जनता को उनका अधिकार वापस किया है। 15 साल हमारी सरकार थी, हमने सरगुजा को नक्सल मुक्त किया और हमारी सरकार रहते नक्सलवाद को बहुत थोड़े से हिस्से में हमने समेट दिया। नक्सलवाद को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पाला पोसा और बढ़ावा दिया है।

पिता कमलनाथ के सपनों को संरक्षित कर विकास कार्य को गति देने मैदान में उतरे नकुलनाथ

(पेज 1 से जारी)

फिर बात चाहे रोजगार की हो, कामकाज की या फिर सुरक्षा, निवेश और व्यापार की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पांच दशकों के अपने अथक प्रयास से जिस तरह से छिंदवाड़ा को विकसित करने का कार्य किया था वर्तमान भाजपा नेतृत्व और उसके नेता कमलनाथ के इस मॉडल को तहस-नहस करने में जुटे हुये हैं। सूत्रों के अनुसार स्थानीय भाजपा सांसद बंटी विवेक साहू जनता के सामने अपनी सकारात्मक छवि बनाने के लिये कमलनाथ द्वारा शुरू किये गये कार्यों को बंद करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।

अवैध वसूली और जमीन अधिग्रहण की मिली शिकायतें

स्थानीय नेताओं के अनुसार जिले में जब से भाजपा नेता ने कमान संभाली है जिले के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अवैध वसूली और जमीन अधिग्रहण जैसी परेशानियां अब सामने आने लगी है। यही नहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा सांसद पूरे जिले में अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन स्थानों पर अधिक विकास कार्यों को करने में जुटे हैं जहां उनके अपने लोग हैं और जहां से उन्हें अधिक वोट मिला है। विकास कार्यों में हो रही इस अनदेखी से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि जब लोग अपनी शिकायतों को लेकर नकुलनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने लोगों की परेशानियों को गंभीरता से लिया स्वयं आमजन के साथ मिलकर दोबारा जिले के विकास की योजना पर कार्य शुरू कर दिया है।

पिता के कार्यों को देंगे विशेष पहचान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छिंदवाड़ा जिले के रहवासियों के दिलों में राज करने वाले कमलनाथ ने अपने पांच दशक के कार्यकाल में जिले के विकास की नींव को जिस ढंग से आकार दिया था अब उसे जीर्ण-क्षीर्ण होने से रोकने नकुलनाथ दोबारा मैदान पर उतर आये हैं। नकुलनाथ ने जिले में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, स्व-रोजगार, कृषि, व्यापार आदि विषयों पर मंथन करने के लिये विशेष टीम गठित करने के संकेत दिये हैं। यह टीम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशन में कार्य करेगी और जिले को संरक्षित कर विशेष पहचान दिलायेगी। जाहिर है कि नकुलनाथ द्वारा किये जा रहे यह प्रयास यदि आकार लेते हैं तो निश्चित ही संपूर्ण जिले को एक विशेष पहचान मिलेगी और नकुलनाथ भी पिता के कार्यों को विशेष पहचान देने में सफल होंगे।

आज भी जनता के दिलों पर राज करते हैं पिता-पुत्र

राजनैतिक विश्लेषकों के अनुसार कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता के लिये जो कार्य किया वह अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। ऐसा कार्य न कभी किसी नेता ने किसी जिले में किया है और न ही भविष्य में इस तरह का कार्य दोबारा होने की संभावना है। यही वजह है कि आज भी पिता-पुत्र जिले की जनता के दिलों पर राज करते हैं।

RO No : 13057/195

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)